

नगरीय विकास के तमाम प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें : मुख्यमंत्री

नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर फोकस रखें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे की गति मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करें। साथ ही, अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर फोकस करें जिससे जनता को समय से इनका लाभ मिले। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शहरों में बुनियादी नगरिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेंज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आवास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं की जरूरत एवं वर्तमान प्रचलन को ध्यान में रखते हुए कार्य करें ताकि बोर्ड की राजस्व में वृद्धि हो सके। साथ ही, हाउसिंग बोर्ड निजी विकासकर्ता से प्रतिस्पर्धा करते हुए आमजन को गुणवत्तायुक्त आवास उचित मूल्य में उपलब्ध करवाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकासकर्ता से प्रतिस्पर्धा संपत्तियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार करें,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रां, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद थे।

परियोजनाओं में नवाचार लाए और इनके विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल करें, ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ मिल सके। शर्मा ने कहा कि जयपुर में द्रव्यवती नदी के दोनों ओर से अतिक्रमण को प्राथमिकता के साथ हटाया जाए, इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से उत्थन किया जाए, ताकि आमजन के साथ ही पर्यटक भी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी पर पौधारोपण के कार्य में भी गति लाई जाए। बैठक में बताया गया कि जयपुर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए आमजन की सुगम आवाजाही के लिए रिव्दि-सिद्धि चौहान पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए कायदेशि जारी किया जा चुका है। साथ ही, अपेक्ष सर्किल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण की डीपीआर के लिए भी कायदेशि जारी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को बेहतर नगरिक सुविधाएं जैसे

सीवरेंज, ड्रेनेज, पार्क, लोक परिवहन हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना शुरु की जाएगी जिससे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव का प्रबंधन हो सके। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में नियमित बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न लंबित बजटीय घोषणाओं के एनआईटी, टेण्डर, वर्कऑर्डर तथा डीपीआर बनाने सहित विभिन्न कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स को चरणबद्ध पूरा करें। साथ ही, हर चरण पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बावाडी एवं विद्याधर नगर (टोडी मोड तक) मेट्रो संचालित की जाएगी। अधिकारी इसके काम में गति लाएं,

ताकि निर्धारित समय में कार्य पूरा हो। उन्होंने जोधपुर के बडली में आवासीय योजना लाने तथा भिवाडी विकास प्राधिकरण के गठन के संबंध में तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 की सभी बजट घोषणाओं में जल्द से जल्द भूमि आवंटित कर कार्य शुरू किया जाए। साथ ही, अधिकारी योजनाओं की अनुमानित लागत के आधार पर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट की विभिन्न घोषणाओं के अंतर्गत बाड़मेर, धौलपुर, फुलेरा सहित अन्य शहरों की विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में भीम-राजसमंद ड्रेनेज सिस्टम, सूरजगढ़-बुंदेलूर में सीवरेंज लाईन, दौसा शहर में सीवरेंज मास्टर प्लान तारानगर-चुरु, नगर व सीकरी-डींग में ड्रेनेज के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सीवरेंज कार्य भी

- शहरी क्षेत्र में पर्याप्त नागरिक सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार, सुनियोजित शहरी विकास को मिल रही गति : मुख्यमंत्री

समयबद्ध रूप से करवाए जाएं, ताकि आमजन को बेहतर यातायात एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, बुंदेलूर में निर्मित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, किसानों की सहभागिता से इस संबंध में एक सेमिनार भी आयोजित किया जाए। शर्मा ने कहा कि बैठक में शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा को मजबूती देने के लिए तथा ई-वसों के सुगम संचालन हेतु मॉडर्न शेल्जर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। बैठक में बजट 2024-25 एवं 2025-26 की नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झावर सिंह खर्रां एवं मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने पकड़ीं प्रतिबंधित दवाइयां

जयपुर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने जयपुर सोडाला से प्रतिबंधित दवाइयां दामाडोल कैप्सूल, अल्फाजोलम टेबलेट की बड़ी खेप व कोडीन फॉस्फेट की बोतलें पकड़ी हैं। साथ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 42 हजार की नगदी भी बरामद की है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुन्देल ने बताया कि जयपुर सेल के अधिकारियों को दो व्यक्तियों के बाइक से सोडाला के छाबड़ा रोड पर प्रतिबंधित दामाडोल ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर टीम मौके पर गई। संदिग्ध की निगरानी रखी। उन्हें जयपुर के छाबड़ा रोड चलंवल पावर हाउस के पास रोका। तलाशी के दौरान वाहन में छुपाए गए 33 डिब्बों में 7 हजार 920 प्रतिबंधित दामाडोल कैप्सूल और 118 कोडीन फॉस्फेट की बोतलें मिली। पूछताछ के बाद एक टीम सप्लायर को पकड़ने के लिए रवाना हुई। उसे पेट्रोल पंप वाले बालाजी, के पास रोका। तलाशी में सप्लायर के पास से दवा बिक्री की रकम 42 हजार 780 बरामद की। सप्लायर ने पूछताछ में स्टॉकिस्ट के बारे में बताया। इसके बाद टीम ने सीकर रोड स्थित एक आवासीय परिसर में छापा मारा। दामाडोल की 2184 कैप्सूल, अल्फाजोलम की 600 गोलियां और कोडीन फॉस्फेट की 97 बोतलें बरामद हुईं।

पतंजलि को मिला अंतरराष्ट्रीय स्तर का ए.ई.ओ. टायर-2 प्रमाणपत्र

व्यावसायिक क्षेत्र में उद्यिमता का नया कीर्तिमान स्थापित किया पतंजलि ने : स्वामी रामदेव

नई दिल्ली। देश की आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के घर-घर में विश्वास का प्रतीक बनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने स्वदेशी इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय- भारतीय सीमा शुल्क ने पतंजलि को ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरैटर टायर-2 (ए.ई.ओ.) प्रमाणपत्र प्रदान किया है। यह प्रमाणपत्र विश्वस्तरीय व्यापार में ईमानदारी, पारदर्शिता और सप्लाई चेन सुरक्षा के उच्चतम मानकों का प्रतीक है। भारत की सर्वोच्च कंपनियों में केवल गिनी-चुनी कंपनियों के पास ही यह दर्जा है, और एफ.एम.सी.जी. सेक्टर में तो यह गौरवशाली प्रमाणपत्र केवल कुछ ही कंपनियों को प्राप्त है। अब इस सूची में पतंजलि का नाम स्वर्ण अक्षरों में जुड़ गया है।

उल्लेखनीय है कि पतंजलि फूड्स को इस एईओ टायर-2 प्रमाणपत्र से सम्मनी को ड्यूटी डिफर्ड पेंमेंट, बैंक गारंटी से छूट, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी , 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन किलरॉस सुविधा के साथ और कुल 28 प्रसार से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लाभ



प्राप्त होंगे। स्वामी रामदेव ने कहा कि यह किसी भी कंपनी की गुणवत्ता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शी कार्यप्रणाली और राष्ट्रहित में योगदान का प्रमाण है। पतंजलि ने अपने गुणवत्ता की प्रामाणिकता ,कर्मयोग, कर्तव्यनिष्ठा और स्वदेशी भावना के बल पर यह विशेष मानक प्राप्त किया है। यह केवल एक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आजादी को और मजबूत करने वाला सम्मान है। स्वामी रामदेव ने कहा कि आज का दिन पतंजलि परिवार के

लिए ही नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के लिए गर्व का दिन है, पतंजलि विश्वसनीयता, प्रमाणिकता, प्रतिस्पर्धा व गुणवत्ता के क्षेत्र में प्रतिदिन नई गति से आगे बढ़ रहा है तथा व्यावसायिक क्षेत्र में उद्यिमता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है ,जो भारत को आर्थिक रूप से विश्वगुरु बनते देखना चाहता है।

आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि “यह उपलब्धि पतंजलि के संपूर्ण परिवार, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सामूहिक साधना का फल है।

परिसीमन के नाम पर लंबे समय तक स्थगित नहीं रख सकते पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि परिसीमन के नाम पर लंबे समय तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित नहीं रखे जा सकते। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि परिसीमन प्रक्रिया समय पर पूरी हो, ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समय पर चुनाव कराए जा सके। जहां पंचायत भंग होती है, वहां आदर्श रूप से छह माह के भीतर चुनाव होने चाहिए।

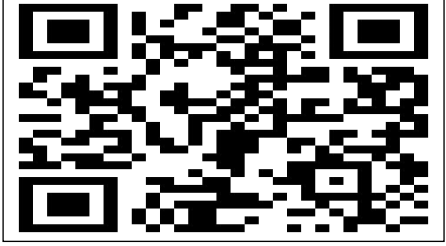
अदालत ने कहा कि निवर्तमान सरपंचों को अपनी पंचायतों के दैनिक कार्य के प्रबंधन के लिए प्रशासक लगाया गया और पंचायतों के विघटन के छह माह बाद उन्हें प्रशासक पद पर होने रहने की अनुमति दी गई, लेकिन बाद में उन्हें तय प्रक्रिया का पालन किए

अनूप मिश्रा मुख्यालय शाखा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित

जयपुर। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के द्वितीय चरण के चुनाव में शाखा मुख्यालय के शाखा अध्यक्ष पद पर अनूप मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित हुए। संघ के संयुक्त महासचिव गोविन्द नाटाणी ने बताया कि 18 अगस्त को मुख्यालय शाखा अध्यक्ष पद के लिए मण्डल मुख्यालय में चुनाव पर्यवेक्षण सुभाष चंद यादव, दारा सिंह, सरोज जैन द्वारा कराये गए। चुनाव में एक मात्र आवेदन प्राप्त होने पर अनूप मिश्रा को शाखा अध्यक्ष मुख्यालय पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। निर्वाचित अध्यक्ष मिश्रा को संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष दशरथ कुमार द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। महामंत्री प्रदीप शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष भगवती प्रसाद द्वारा नव निर्वाचित मुख्यालय अध्यक्ष अनूप मिश्रा को शुभकामनाएं दी गई। मिश्रा द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि मण्डल हित एवं कर्मचारी हित में अपना योगदान देते रहेंगे एवं समय-समय पर मण्डल हित एवं कर्मचारी हित के लिये आवाज उठाते रहेंगे।

मुरलीपुरा में स्कॉर्पियो कार से मजदूर को कुचलने वाला बदमाश गिरफ्तार

रेडियो मिर्ची और संजीवनी बिल्डहोम की सेना के जवानों के लिए अनूठी पहल



जयपुर। रेडियो के इतिहास में पहली बार, मिर्ची और संजीवनी बिल्डहोम लेकर आए हैं “मिर्ची प्लॉट 983”, उनके लिए घर, जो रहते हैं सरहद पर। आम तौर पर रेडियो स्टेशनों में रेडियो मिर्ची का नाम संगीत और मनोरंजन के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को न सिर्फ रेडियो पर बल्कि, ऑन ग्राउंड और डिजिटल मीडियम पर सफलता पूर्वक करने के लिए प्रमुखता से जाना जाता रहा है, लेकिन इस बार रेडियो मिर्ची जयपुर ने एक अनोखी पहल शुरू की है। संजीवनी बिल्डहोम के साथ मिलकर मिर्ची ने एक ऐसा अभियान

- “मिर्ची प्लॉट 983” अभियान के तहत सेना के जवानों को एक अनमोल तोहफा दिया जाएगा

चलाया है जो हमारे देश के वीर जवानों को उनकी शानदार सेवाओं के लिए सम्मानित करता है।

इस अभियान के तहत, जिसका नाम “मिर्ची प्लॉट 983” है, देश के लिए दिन-रात सरहद पर खड़े रहने वाले जवानों को एक अनमोल तोहफा दिया जाएगा। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर कोई

भी व्यक्ति अपने किसी जानकर, जो भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना या किसी भी भारतीय सेना इकाई का हिस्सा है, वे नॉमिनेट कर सकते हैं।

संजीवनी बिल्डहोम और मिर्ची जयपुर का ये सहयोग एक भाग्यशाली विजेता को जयपुर में एक पूरा प्लॉट जीतने का मौका देगा। ये पहल न सिर्फ जवानों के लिए सम्मान का प्रतीक है, बल्कि देश के लोगों को उनके योगदान के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास भी है। इस खबर के साथ दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने परिवार या किसी जानने वाले को नॉमिनेट कर सकते हैं।

15 हजार का फरार इनामी बदमाश लाभचंद गिरफ्तार

जयपुर। एंटी टैरिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) राजस्थान ने लंबे समय से फरार इनामी व मादक पदार्थ तस्करी में वांछित आरोपित लाभचन्द को दबोचा है। आरोपित की गिरफ्तारी पर पुलिस केन्द्रीक्षक श्री गंगानगर से 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

एटीएस पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि एटीएस राजस्थान ने इनामी व मादक पदार्थ तस्करी में वांछित आरोपित लाभचंद (41) निवासी बँगू जिला चित्तौड़गढ़ की गिरफ्तार किया है। आरोपित लाभचन्द, पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़कर खेती-बाड़ी करने लगा । पैसों की कमी के चलते जाना चाहता था, पर अन्दर-ही-अन्दर पकड़े जाने का डर भी सता रहा था। आरोपित लाभचन्द न तो पैसा सका सका और न ही ऐसे आराम की ज़िंदगी जी पाया। उल्टा फरारी के दौरान पुलिस के भय से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। आरोपित लाभचन्द को पूर्व में भी लगभग 2.6 किंवदंल अफीम दूध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा

- आरोपी पूर्व में भी 2.6 किंवदंल अफीम दूध की तस्करी में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के हथे चढ़ चुका है

गिरफ्तार किया था।

कुमार ने बताया कि एटीएस टीम के विश्लेषण से यह सामने आया कि लाभचन्द अपनी पत्नी के मिलने के लिये अपने दूर के रिश्तेदार के वहां जाता है तथा पत्नी को भी वहीं भुला लेता हैं। इस पर एटीएस टीम ने छत्र भेष में लाभचन्द के परिवार के आवागमन पर निगरानी रखनी शुरू की। जहां लाभचन्द की पत्नी बीमार है व उसके ईलाज के लिये उसको भीलवाड़ा डॉक्टर को दिखाने जाता है। एटीएस टीम को सूचना मिली कि लाभचन्द पुलिस के भय से घर के आसपास फरारी काट रहा है, इसी आसूचना के आधार पर उसके संभावित ठिकाने पर दबिश देकर आरोपी को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की।

- “अदालत ने कहा कि जहां पंचायत भंग होती है, वहां आदर्श रूप से 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि परिसीमन प्रक्रिया समय पर पूरी हो।”

बिना हटा दिया गया।

अदालत ने याचिकाकर्ता प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश को रद्द करते हुए पंचायती राज कानून की धारा 38 के तहत याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई की छूट दी है। अदालत ने कहा कि दो माह में याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद मामले में कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अदालत ने आशा जताई है कि राज्य सरकार मामले में गौर करेगी। वहीं अदालत ने आदेश की कॉपी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग,

राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को भेजी है। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने यह आदेश महावीर प्रसाद गौतम व 16 अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा व अन्य ने बताया कि सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद विभाग ने चुनाव में देरी को देखते हुए गत 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगा दिया। वहीं बाद में उन्हें

बिना जांच और सुनवाई का मौका दिए प्रशासक पद से हटा दिया गया। याचिका में कहा गया कि उनकी नियुक्ति की अधिसूचना वैधानिक रूप से मान्य थी।

ऐसे में उन्हें बिना जांच हटाना अवैध है। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक लगाया गया था और जिस परिपत्र से उन्हें नियुक्त किया गया था, वह वैधानिक नहीं था। वहीं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश को रद्द करते हुए अन्य दिशा-निर्देश दिए हैं।

दो करोड़ की मिट्टी खुदाई के टैंडर में 2 फर्मों की समान रेट आई, अब ठेका पाने की जुगाड़ में जुटे दोनों ठेकेदार

- वित्त निदेशक 2 बार इसी तरह के टैंडर ज्यादा दर आने के कारण कर चुके हैं निरस्त, अब भी करें तो होगा जे.डी.ए. को फायदा

अथवा निचले क्षेत्रों में जेडीए के प्लॉट्स में डालनी है।

बताया जा रहा है कि इस काम को लेने के लिए पांच ठेकेदारों ने टैंडर भरा था। ऐसे में करीब 35 फीसदी कम रेट ठेके में सामने आयी। परंतु दो फर्मों ने एक समान रेट भरी, जिसमें निराला एंटरप्राइजेज 35.99 और शिवा कंस्ट्रक्शन की रेट 35.99 आई है। अब ये दोनों फर्म टैंडर लेने की जुगाड़ में जुटी हुई हैं। इन्होंने पहले ही निर्धारित दर से कम रेट पर बिड डाली है। अब

दोनों फर्म इससे भी कम रेट पर नेगोशिएशन को तैयार है। इसका कारण यहां बड़ी मात्रा में मिट्टी के टीले होना है। ये दोनों ठेकेदार किसी भी स्तर पर ये ठेका लेना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि वित्त निदेशक 2 बार इसी तरह के टैंडर ज्यादा दर आने के कारण कर निरस्त चुके हैं। ऐसे में अब भी यहां ठेका निरस्त किया जायेगा तो जेडीए को राजस्व का फायदा होगा।

गौरलब है कि जौन-12 स्थित केदार विहार और अवंतिका विहार में इन दिनों मिट्टी के अवैध खनन और रेत माफिया द्वारा मिट्टी के डंपर परकट बाहर ले जाने का मामला भी सामने आया है।

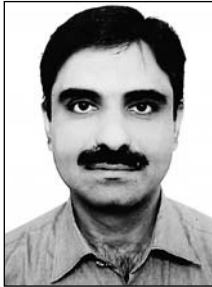
को कुचलने वाले चालक और अन्य के खिलाफ पुलिस ने हथ्था का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कार चलाने वाले आरोपित कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मारपीट करने वाले सुभाष और एक अन्य व्यक्ति की तलाश पुलिस टीम में कर रही है। इस घटना के बाद आरोपित कार लेकर जयपुर से बाहर निकल गए थे। पुलिस की तीन टीम जगह-जगह आरोपित युवकों की तलाश में दबिश दे रही है।



डॉ. नीतीश शर्मा



अमिता शर्मा



नरेन्द्र कुमार



नरेश गोयल

जयपुर (कास)। राजस्थान में अन्य सेवाओं से चार अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) बनाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गैर राज्य प्रशासनिक सेवाओं के चार अफसरों को आई.ए.एस. बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। 18 अगस्त को जारी हुई इस अधिसूचना के अनुसार डॉ. नीतेश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मंधानी और नरेश कुमार

गोयल को आई.ए.एस. बनाया है। डॉ. नीतेश शर्मा सांख्यिकी सेवा और अमिता शर्मा लेखा सेवा की अफसर है। चारों अफसरों को वर्ष 2022 की वेंकैसी के तहत आई.ए.एस. बनाया गया है। पिछले महीने दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) की बैठक में इन चारों अफसरों के चयन पर अंतिम मुहर लगाई गई थी। अब डी.ओ.पी.टी. ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

इन अफसरों को अभी प्रोबेशन पर रखा जाएगा। इन्हें नए सिरे से पोस्टिंग दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ. नीतीश शर्मा वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय (सी.एम.ओ.) में डायरेक्टर स्टेटिस्टिक्स के पद पर काम कर रहे हैं। वे इकोनॉमिक्स में एम.ए. तथा पी.एच.डी. होने के साथ-साथ एम.बी.ए. फाइनेंस भी है। मुख्यमंत्री

कार्यालय से पहले डॉ. नीतीश ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डायरेक्टर प्रोग्राम मॉनिटरिंग के पद पर 6 साल काम किया है। जिसमें मुख्य सचिव के सीधे निर्देशन में कार्य करते हुए राज्य के सभी कार्यक्रमों, स्क्रीम और प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की है। डॉ. नीतीश को 3 राज्य प्रोत्सर भी राज्पाल व मुख्यमंत्री के हाथों प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सिविल सिर्विसेज दे पर प्राप्त अवार्ड उल्लेखनीय है।